नियम 324 के अन्तर्गत माननीय विधानसभा सदस्य श्री रोहित ठाकुर द्वारा उठाया गया मामलाः

"जुब्बल–कोटखाई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत एंटी हेल नेट्स को मुख्यमन्त्री ग्रीनहाऊस नवीनीकरण/नूतन पॉलीहाऊस योजनाओं की तर्ज़ पर पुनः उपदान प्रदान करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे"

माननीय अध्यक्ष महोदय,

प्रदेश में बागवानी के अन्तर्गत 2,34,779 है० क्षेत्रफल है तथा फल उत्पादन 6,24,485 मी० टन है। जिसमे से 1,14,646 है० क्षेत्रफल केवल सेब की बागवानी के अन्तर्गत है तथा सेब फल उत्पादन 4,81,062 मी० टन है। फल–फसलों को ओलावृष्टि से बचाने में एंटी हेल नेट्स कारगर सिद्व हुए है। वर्ष 2012–13 से सरकार द्वारा एंटी हेल नेट्स पर अनुदान दिया जा रहा है, पहले यह अनुदान केन्द्र सरकार की योजना MIDH (एकीकृत बागवानी विकास मिशन) के अन्तर्गत दिया जाता था परन्तु समय के साथ एंटी हेल नेट्स की मांग में काफी बढ़ोतरी हुई है जिसके मध्येनजर वर्तमान सरकार ने वर्ष 2018–19 में प्रदेश सरकार प्रायोजित एंटी हेल नेट्स स्कीम को आरम्भ किया जिसमें 80% (छोटे एवं सीमांत बागवान को) तथा 50% (बड़े बागवान को) का अनुदान अधिकतम 28 रू० प्रति वर्गमीटर तथा 17.50 रू प्रति वर्गमीटर एंटी हेल नेट क्रमशः, की दर से प्रदान किया जाता है। जुब्बल–कोटखाई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 से 2021–22 तक एंटी हेल नेट योजना के अन्तर्गत 1103.69 लाख रू० की राशि व्यय कर 1240 बागवानों को लाभान्वित किया जा चुका है जबकि उपरोक्त विधानसभा निर्वाचान क्षेत्र में एंटी हेल नेट के 751 मामले लम्बित पडे है व 668.02 लाख रू० की अनुदान राशि देय है। इस योजना में वर्तमान वर्ष व पिछले 3 वर्षों में दी गई अनुदान राशि व लाभार्थियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

क्र० सं०	वर्ष	आबंटित राशि (लाख रूपये)	व्यय राशि (लाख रूपये)	लाभार्थियों की संख्या
1	2018–19	2400.00	2400.00	3635
2	2019–20	2044.21	2044.21	3229
3	2020–21	2000.00	2000.00	2426
4	2021–22	2000.00	1556.83	1819

नोटः वर्ष 2021–22 की शेष राशि का व्यय किया जा रहा है।

जहां तक एंटी हेल नेट्स पर मुख्यमन्त्री ग्रीनहाऊस नवीनीकरण/ नूतन पॉलीहाऊस योजनाओं की तर्ज़ पर पुनः उपदान प्रदान करने के विषय में यह व्यक्त किया जाता है कि अभी भी 3314 बागवानो की एंटी हेल नेट की मांग है जिस पर 2707 लाख रूपये की अनुदान राशि देय है इसलिए नष्ट हुए एन्टी हेल नेट्स पर पुनः उन बागवानों को उपदान देना वर्तमान में उचित नहीं होगा। अतः सरकार का अभी इस प्रकार की योजना आरम्भ करने का कोई विचार नहीं है।

*****